RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 25 MARCH TO 31 MARCH 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 31 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

बाजार में एक दिन में एक दशक की सबसे बड़ी तेजी, सेंसेक्स 1862 अंक उछला
Page 2

जानलेवा वायरस की दवा बनाने में जुटे कई देश, भारत भी कर रहा कोशिश
Page 4

लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हो सकता है नौ लाख करोड़ रुपये का नुकसान
Page 5

editoria!

ढीला न पड़े अर्थतंत्र

देश में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी हर स्तर पर चल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके असर से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। सोमवार को उसने लांग टर्म रेपो ऑपरेशन (एलटीआरओ) का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। एलटीआरओ एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों को एक से तीन साल के लिए वर्तमान रेपो रेट (5.15 प्रतिशत) पर कर्ज उपलब्ध कराता है। बदले में बैंक कोलैटरल के तौर पर अपने पास मौजूद पब्लिक सिक्युरिटीज यानी सरकारी बॉन्ड रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखते हैं। इस कदम का उद्देश्य बैंकों को अपनी ब्याज दरें घटाने के लिए प्रेरित करना है। इसके पहले रिजर्व बैंक चार बार, 17 फरवरी, 24 फरवरी, 1 मार्च और 9 मार्च को एलटीआरओ का संचालन कर चुका है। इस सस्ते फंड के बल पर बैंकों ने अगर अपना कर्ज सस्ता किया तो बाजार में कुछ गति आ सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नए एलटीआरओ के जरिए कई हिस्सों में एक लाख करोड़ रुपये सिस्टम में डाले जाएंगे। इसके अलावा आरबीआई ने छह महीने तक दो अरब डॉलर की खरीद-बिक्री करने का फैसला किया है, जिसका मकसद देश के विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में तरलता बनाए रखना और डॉलर की जरूरतों को आसान बनाना है। डॉलर के मुकाबले रुपये में जो तेज गिरावट देखी जा रही है, उस पर आरबीआई के इस कदम से कुछ लगाम लगेगी। शक्तिकांत दास के मुताबिक देश के कई हिस्सों में नीलामी के जरिए डॉलर की खरीद-बिक्री (स्वैप) की जाएगी। कोरोना वायरस से इंडस्ट्री पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए सरकार ने सेक्टोरल पैकेज की तैयारी शुरू की है। सरकार अलग-अलग सेक्टरों के लिए खास योजनाएं बनाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कुछ क्षेत्रों पर खास फोकस किया जाएगा, जैसे फार्मा इंडस्ट्री। दवा कंपनियां अपना 75 फीसदी कच्चा माल (एपीआई) बाहर से मंगाती हैं। सरकार इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई कंपनियां लगाने वालों को विशेष रियायत देगी। इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट बनाने वाली कंपनियों पर भी सरकार की नजर है। उनके लिए तीन स्कीमें सरकार ने तैयार की हैं। एक्सपोर्ट-इंपोर्ट सेक्टर के लिए भी सरकार खास तैयारी कर रही है जिसमें कपड़ा, चमड़ा और केमिकल्स के एक्सपोर्ट पर ज्यादा जोर रहेगा। सरकार ने चाइना वन प्लस पॉलिसी भी बनाई है। इसके तहत चीन में उत्पादन करने वाली कंपनियों को भारत में काम शुरू करने पर विशेष रियायत दी जाएगी। सरकार को ध्यान रखना होगा कि मौजूदा संकट से लोगों की नौकरियां न जाएं। सर्विस सेक्टर पर खास तौर से नजर बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रसार से सबसे ज्यादा संकट उसी पर आया है।

कोरोना से मुकाबले के लिए मोदी सरकार जारी कर सकती है 20 बिलियन डॉलर का पैकेज

एजेंसी, नई दिल्ली।

देश इस वक्त कोरोना वायरस के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की तरफ से कई पहल की गई हैं। लेकिन, आर्थिक मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार इसको लेकर बड़ा कदम उठा सकती हैं। समाचार एजेंसी रायटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस के कारण भारत सरकार 1.5 ट्रिलियन रुपए (19.6 बिलियन डॉलर) का प्रोत्साहन पैकेज दे सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक पैकेज फाइनल नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफि इंडिया के बीच बातचीत जारी है। रायटर्स ने एक सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रोत्साहन पैकेज करब 2.3 ट्रिलियन रुपए का हो सकता है, लेकिन इस पर अभी चर्चा की जा रही है। पैकेज का ऐलान इस हफ्ते के आखिर तक किया जा सकता है और उन पैसों को सीधे 100 मिलियन गरीबों के बैंक एकाउंट्स में भेजा जाएगा और लॉकडाउन से प्रभावित व्यवसायियों की मदद के लिए दिया जाएगा। सरकार एक अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उधार लेने की राशि को भी बढ़ा सकती है, जो वर्तमान में औसत उधार योजना 7.8 ट्रिलियन रुपए की है। रायटर्स ने आगे बताया ह कि सरकार ने केन्द्रीय बैंक से कहा कि वे जारी किए जा रहे सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदे। यह सरकार का एक ऐसा कदम है जिसे कई दशकों से भारतीय केन्द्रीय बैंक की तरफ से महंगाई बढ़ने के चलते नहीं उठाया गया है। भारत में कोरोना को लेकर काफी संकट की स्थिति बनी हुई है। पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। देश में अब तक कोरोना के 605 मामलों की पुष्टि हो चुकी है जबकि 10 लोगों की मौत हो गई है।

अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा से पहले महंगा हुआ कच्चा तेल

सिंगापुर। एजेंसी

कोरोना वायरस की मार से झेल रहे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा से पहले एशिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.9 फीसदी

उछाल के साथ 28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी बेंच मार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 3.5 पर्सेंट चढ़कर 25 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया।

दोनों ही बेंचमार्क में हाल के कुछ सप्ताह में भारी गिरावट आई है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंधों के अलावा सऊदी अरब और रूस के बीच प्राइस वॉर की वजह से कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई साल के निचले स्तर पर आ गई हैं।

बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में यह वृद्धि अमेरिकी शेयर बाजार में 11.4 पर्सेंट की तेजी के बाद आई। यह 1933 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी छलांग है। शेयर बाजार में यह ऐतिहासिक तेजी प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की उम्मीद में आई है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में दोबारा जान फूंकने के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के पैकेज की घोषणा हो सकती है, कांग्रेस इस समझौते के करीब है।

शेयर बाजार में तेजी की वजह से उ7 की ओर से किया गया वादा भी है, जिसमें कहा गया है कि हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा सोमवार को फेडरल रिजर्व बैंक ने भी संकट की इस घड़ी से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए खजाना खोलने की बात कही। इससे भी निवेशकों में उत्साह बना है।

कच्चा तेल उत्पादन फरवरी में 6.4 प्रतिशत घटा

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश का कच्चा तेल उत्पादन फरवरी में एक साल पहले की तुलना में 6.4 प्रतिशत गिर गया। इसकी प्रमुख वजह निजी कंपनियों के परिचलन वाले तेल कुंओं का उत्पादन घटना है। हालांकि इस अवधि में ओएनजीसी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में देश का कच्चा तेल उत्पादन सालाना आधार पर 6.41 प्रतिशत घटकर 23.9 लाख टन रह गया। पिछले साल फरवरी में यह 25.6 लाख टन था। सरकारी कंपनी ओएनजीसी का तेल उत्पादन इस दौरान 4.64 प्रतिशत बढ़कर 16.7 लाख टन रहा। हालांकि निजी क्षेत्र के नियंत्रण वाले तेल कुंओं का उत्पादन 32.6 प्रतिशत गिर गया है।जबकि राजस्थान के तेल कुंओं का उत्पादन 32.3 प्रतिशत गिरा है। राजस्थान के तेल क्षेत्र का नियंत्रण वेदांता लिमिटेड के पास है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का कच्चा तेल उत्पादन फरवरी में 13.13 प्रतिशत गिरकर 2,46,260 टन रहा।इस दौरान प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन भी करीब नौ प्रतिशत घटा है। फरवरी में यह 2.2 अरब घन मीटर रहा।

गरीब परिवारों को सस्ते में मिलेगा गेहूं, चावल

ठेके पर काम करने वालों को मिलेगा वेतन

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को अगले तीन माह तक दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही देश की 80 करोड़ आबादी को चावल भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को उनका वेतन दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 1,340 करोड़ रुपये डालने के प्रस्ताव को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। इससे ग्रामीण बैंकों की पूंजीगत स्थिति बेहतर होगी।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बाजार में एक दिन में एक दशक की सबसे बड़ी तेजी, सेंसेक्स 1862 अंक उछला

मुंबई। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को जोरदार तेजी आयी। यह किसी एक दिन में एक दशक की सबसे बड़ी तेजी है। वैश्विक बाजारों में मजबूती और कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये सरकार के प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद में बाजार में उछाल आया। बीएसई सेंसेक्स में कारोबार की शुरूआत में उतार-चढ़ाव देखा गया। पर अंत में यह 1,861.75 अंक यानी 6.98 प्रतिशत मजबूत होकर 28,535.78 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 516.80 अंक यानी 6.62 प्रतिशत मजबूत होकर 8,317.85 अंक पर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों में यह तेजी किसी एक दिन में एक दशक की सबसे बड़ी तेजी है। वैश्विक बाजारों में तेजी का भी घरेलू बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अमेरिका में सरकार और संसद के ऊपरी सदन सीनेट के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 2,000 अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज को लेकर समझौते की घोषणा से वैश्विक बाजारों में तेजी आयी।

सेंसेक्स के शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे लाभ में रही। कंपनी का शेयर 15 प्रतिशत मजबूत हुआ। उसके बाद कोटक बैंक, मारुति, एचडीएफसी बैंक और एसडीएफसी, टाइटन, एल एंड टी और एक्सिस बैंक का स्थान रहा। वहीं दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, आईटीसी और बजाज ऑटो नुकसान में रहे। सभी खंडवार सूचकांकों में तेजी रही। ऊर्जा, वित्त, बैंक, वाहन और तेल वं गैस सूचकांकों में 10 प्रतिशत तक की तेजी आयी। आनंद राठी के प्रमुख इक्विटी रिसर्च नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि कोरोना संबधी सार्वजनिक पाबंदी की नये सिरे से घोषणा से अनिश्चितता कम हुई है। साथ ही सरकार के प्रोत्साहन उपायों के आश्वासन से निवेशकों की धारणा सुधरी है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कोरोना वायरस संकट से निपटने और एक-दूसरे से होने वाले संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिये 21 दिन के बंद की घोषणा की। सोलंकी ने कहा कि वायदा एवं विकल्प खंड के अनुबंधों के कल (बृहस्पतिवार) समाप्त होने से पहले 'शार्ट कवरिंग' सौदों को पूरा करने के लिये खरीदारी से बाजार में आयी यह तेजी चौतरफा रही। बड़ी, मझोली एवं छोटी कंपनियों के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गयी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस झटके से उबारने के लिये जल्दी ही वित्तीय पैकेज की घोषणा करेगी। व्हाइट हाउस और सीनेट के बीच कोरोनो वायरस महामारी के अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिये 2,000 अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज से जुड़े विधेयक पर सहमत होने से वैश्विक बाजारों में तेजी आयी। जिसका असर भी घरेलू बाजार पर पड़ा। एशिया के अन्य बाजारों में चीन के शांघाई, हांगकांग, जापान के तोक्यो और दक्षिण कोरिया के सोल बाजार के प्रमुख सूचकांक 8 प्रतिशत तक मजबूत हुए। शुरूआती कारोबार में यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी 4 प्रतिशत तक की तेजी चल रही थी। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव 0.07 प्रतिशत मजबूत होकर 27.17 डॉलर बैरल पर पहुंच गया। घरेलू मुद्रा बाजार गुड़ी पड़वा के अवसर पर बुधवार को बंद है। इधर, स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण मामलों की संख्या बढ़कर 562 पहुंच गयी है जबकि मरने वालों की संख्या 10 से कम कर 9 कर दी गयी है। दिल्ली में दूसरी मौत में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं पाया गया। वहीं दुनिया में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,20,000 हो गयी है जबकि 18,000 लोगों की मौत हुई है।

कृषि रसायन कंपनियों ने कोरोना प्रतिबंधों से छूट की मांग की

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कृषि रसायन बनाने वाली कंपनियों के संगठन क्राप लाइफ इंडिया ने बुधवार को सरकार से आग्रह किया कि उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए निषेधाज्ञा से छूट मिले और उन्हें अपना उत्पादन , वितरण और बिक्री के कार्य जारी रखने दिया जाए। संगठन ने यह मांग आने वाले खरीफ बुवाई सीजन से पहले की है। क्रापलाइफ इंडिया के मुख्य कार्यपालक ए सेन ने एक बयान में कहा कि खरीफ का सीजन आने ही वाला है। अगले तीन माह किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में कृषि क्षेत्र में काम आने वाले रसायनों से जुड़ी सभी गतिविधियों को पाबंदी से मुक्त रखा जाए। संगठन में 18 कंपनियां जुड़ी हैं। ये कृषि रसायानों पर अनुसंधान एवं विकास का कार्य भी करती हैं सरकार ने कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के उद्देश्य से आवागमन पर 21 दिन के लिए देशव्यापी रोक लगा दी है। भारत में अब तक कारोना संक्रमण के 562 मामले पुष्ट हुए है।

अमेरिका में भारी-भरकम राहत पैकेज से एशियाई बाजारों को भी मिली राहत

हांगकांग। एजेंसी

अमेरिका में कोरोना वायरस के आर्थिक असर को कम करने के लिये भारी-भरकम राहत पैकेज की तैयारी से अमेरिका और यूरोप के बाजारों उत्साह का संचार हुआ। इससे समर्थन पाकर एशियाई बाजार बुधवार को भी तेजी में रहे। अमेरिका में सांसद दो हजार अरब डॉलर के राहत पैकेज को अंतिम रूप देने के करीब हैं। यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के आकार के करीब 10 प्रतिशत के बराबर का राहत पैकेज हो सकता है। इससे वैश्विक बाजारों में तबाही भरे कुछ सप्ताहों के बाद ऊर्जा का संचार हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट सदस्य चक शूमर ने अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन से मुलाकात के बाद सदन को बताया, ''इस समय कुछ ही मुद्दे बचे हैं, जिन पर सहमति नहीं बन पायी है। मुझे नहीं लगता कि इनके से किसी भी असहमति को अगले कुछ घंटे में दूर नहीं कर लिया जाएगा।'' फेडरल रिजर्व द्वारा जितनी जरूरत होगी, उतनी नकदी छापने की दृढ़ इच्छा दिखाने के साथ ही इस भारी-भरकम राहत पैकेज की उम्मीद के ठोस हो जाने से मंगलवार को वॉल स्ट्रीट में शानदार तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में मंगलवार को 1933 के बाद की सबसे बड़ी प्रतिशत बढ़त देखने को मिली। एसएंडपी 500 के लिये भी यह दशक से अधिक का सबसे अच्छा दिन साबित हुआ। इसका असर एशियाई बाजारों में भी देखने को मिला और लगातार दूसरे दिन तेजी जारी रही।जापान का निक्की 5.7 प्रतिशत की बढ़त में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शेयर बाजार, सिंगापुर शेयर बाजार और न्यूजीलैंड का वेलिंगटन शेयर बाजार दो प्रतिशत से अधिक की तेजी में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और ताईवान शेयर बाजार चार प्रतिशत से अधिक चढ़ गया। चीन का शंघाई कंपोजिट भी दो प्रतिशत से कुछ अधिक की बढ़त में रहा।

अमेरिका में 20 खरब डॉलर के विशेष पैकेज का ऐलान, बेरोजगारों को मिलेगी सीधे मदद

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। लॉकडाउन के कारण व्यवसाय और स्वास्थ्य प्रणाली को पटरी पर लाने के लिए 20 खरब डॉलर विशेष पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिकी सीनेट के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसको हरी झंडी दे दी है। अभूतपूर्व आर्थिक बचाव पैकेज अधिकांश अमेरिकियों को प्रत्यक्ष भुगतान देगा। श्रमिकों को आर्थिक तंगी से उबारा जाएगा। इससे बेरोजगारी से निपटने और छोटे व्यवसायों को उबारने में मदद मिलेगी। अस्पतालों को भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

गरीब परिवारों को सस्ते में मिलेगा गेहूं, चावल

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि कैबिनेट ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के हिस्से से 670 करोड़ रुपये के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने गार्मेंट्स, मेडअप्स के निर्यात पर केंद्रीय एवं राज्य के करों पर छूट की योजना की समयसीमा बढ़ाए जाने को भी अपनी मंजूरी दे दी। जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाइओवर के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी। यह फ्लाइओवर कुल 22 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अगले पांच साल में पूरा होने की संभावना है।

14 अप्रैल तक बंद रहेगी रेलवे की यात्री सेवा, मालगाड़ियां चलती रहेंगी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर रेलवे ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसकी मेल, एक्सप्रेस तथा पैसेंजर सेवाएं अब 14 अप्रैल तक बंद रहेगी। देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद रेलवे का यह कदम सामने आया है। अधिकारियों ने हालांकि कहा है कि देशभर में मालगाड़ी की सेवा बरकरार रहेगी।

ऑनलाइन बुकिंग का पैसा खुद मिलेगा

इससे पहले, रेलवे ने 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मालगाड़ी छोड़कर सभी पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला किया था। इस निलंबन में सभी उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी शामिल हैं। इस बीच, भारतीय

रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने लोगों से कहा है कि वे ट्रेनों की ऑनलाइन बुक की गई टिकटों को रद्द न करें और उन्हें खुद ही पूरा पैसा मिल जाएगा।

जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति

भारतीय रेलवे ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से सभी यात्री सेवाओं को निलंबित करने के लिए बाध्य होने के बावजूद वह देश में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। रेलवे ने बताया कि 23 मार्च को अनाज, नमक, खाद्य तेल, चीनी, दूध, फल और सब्जियां, प्याज, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों के 474 रैक तैयार किए गए।

कोरोना से लड़ाई में रेलवे सरकार के साथ

रेलवे बोर्ड ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए अपनी सभी निर्माण इकाइयों को निर्देश जारी कर अस्पताल के सामान्य बेड, मेडिकल ट्रॉली और पृथक सुविधाएं तथा आईवी स्टैंड जैसी चीजों के निर्माण की संभावना का पता लगाने को कहा है।

CORONA EFFECT

GST, Income Tax रिटर्न फाइल करने की मियाद बढ़ी

बैंक ग्राहकों को भी बड़ी राहत

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इनकम टैक्स एवं जीएसटी के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कई तरह के राहत का ऐलान किया। सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। इस अवधि में विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12 फीसद से घटाकर नौ फीसद कर दिया गया है। ऊअए जमा करने के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई लेकिन ब्याज को 18 फीसद से घटाकर नौ फीसद किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा, PAN Card को Aadhaar से लिंक कराने की मियाद भी बढ़ा दी है। इसके अलावा बैंक कस्टमर्स के लिए भी राहत भरी खबर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोनावायरस की वजह से नए तरह के संकट में फंसती दिख रही है। उल्लेखनीय है कि भारत पहले ही GDP Growth में कमी की समस्या से जूझ रहा है।

आइए जानते हैं वैधानिक एवं रेगुलेटरी मोर्चों पर सरकार ने किस तरह की राहत दी है:

■तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई ट्रांजैक्शन चार्ज। ■तीन महीने तक मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करने से मोहलत। ■डिजिटल ट्रांजैक्शन चार्जेज में कमी की गई है। ■सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला किया है। ■इसी के साथ आधार-पैन को लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया। ■विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है। ■'सबका विश्वास' स्कीम से जुड़े विवादों को निपटाने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया। यह सीमा पहले 31 मार्च, 2020 तक थी। ■सरकार ने बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को 2 तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है। ■सीमाशुल्क के मुद्दे पर भी सरकार ने कई तरह की राहत का ऐलान किया। ■कंपनियों के डायरेक्टर्स को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है। ■30 अप्रैल को मेच्योर होने वाले डिबेंचर्स को 30 जून, 2020 तक को बढ़ाया गया। ■वित्त मंत्री ने कंपनियों के लिए डिपोजिट रिजर्व की शर्तों में छूट की घोषणा की। ■नई कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया गया। ■एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनी को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। ■वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मत्स्य क्षेत्र के लिए भी कई तरह के राहत का ऐलान किया।

कोरोना वायरस प्रभाव

जन संपर्क, मनोरंजन उद्योग ने सरकार से मदद की गुहार लगायी

मुंबई। एजेंसी

जन संपर्क और मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन की सेवाएं देने वाले उद्योग ने सरकार से तत्काल मदद का आग्रह करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में 6 करोड़ लोग कार्यरत हैं और कोरोना वायरस महामारी के चलते लगी निषेधाज्ञा के कारण इस उद्योग का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। उनके संगठ इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमैंट एसोसिएशन के अनुसार उद्योग से जुड़े 6 करोड़ कर्मचारियों में से एक करोड़ सीधे तौर पर प्रभावित हैं और उनकी आजीविका खतरे में है। इसका कारण कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम या तो टल गये हैं या फिर रद्द हो गये हैं। एसोसिएशन ने कहा कि पिछले दो महीनों में ही कम-से-कम 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।संगठन ने कहा, "कोरोना वायरस महामारी से उनके कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कई वैश्विक और राष्ट्रीय कार्यक्रम टल गये हैं या फिर स्थगित हो गये हैं।" उसने कहा, "यह प्रतिकूल प्रभाव आने वाले महीनों में भी जारी रहने की आशंका है। क्षेत्र में काम करीब 100 इकाइयों के बीच किये गये सर्वे के अनुसार सिर्फ दो महीनो में ही 3,000 से 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।" महामारी के कारण सार्वजनिक, निजी सम्मेलनों के अलावा अंतरराष्ट्रीय बैठकें, सम्मेलन और प्रदर्शनी कार्यक्रम रद्द हुए हैं। इससे उद्योग हिल गया है। उद्योग में एक करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। जबकि 5 करोड़ लोगों को होटल, पर्यटन, विज्ञापन और विपणन उद्योग जैसे संबद्ध क्षेत्रों में परोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। हाल में जो बड़े कार्यक्रम रद्द हुए हैं, उनमें आईपीएल, आईआईएफए, इंडिया गेमिंग एक्सपो, इंडिया फैशन वीक, गोवा फेस्ट, पीयू टेक, आईटीबी इंडिया, इंडिया फिनटेक फेस्टिवल भारती-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच, इंडिया टुडे सम्मेलन आदि शामिल हैं।

मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के निर्यात पर प्रतिबंध

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर घरेलू बाजार में दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय चिकित्सा शोध परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक बलराम भार्गव ने सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध या पुष्ट मामलों में देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के इस्तेमाल की सिफारिश की थी। आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 पर गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा की गई इलाज की सिफारिशों को भारतीय दवा महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए मंजूरी दी है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया, 'हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन बनाने वाले घटकों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।' अधिसूचना में हालांकि, यह कहा गया है कि सरकार विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर मानवीय आधार पर दवा के निर्यात की अनुमति देगी।

अब सामानों की Home Delivery

भारी संख्या में मिल रहे हैं ऑर्डर्स

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उद्देश्य से इसके संक्रमण की चेन को रोकने के लिए देश भर में 21 दिन के लिए लागू संपूर्ण लॉकडाउन के कारण फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिगबास्केट और ग्रोफर्स द्वारा अपनी सेवाओं को स्थगित कर दिया है या इसमें कटौती कर दी है। इस कारण ऑनलाइन डिलिवरी की सेवाएं बहुत घट गई हैं। इस बीच सुपरमार्केट चेन बिग बाजार मैदान में उतर गया है। बिग बाजार ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में ऑनलाइन डिलिवरी सर्विस लॉन्च की है। अपनी यह सर्विस लॉन्च करने के कुछ देर बाद ही कंपनी के पास डिलिवरी के लिए फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। इसके बाद कंपनी को बुधवार को एक स्टेटमेंट जारी कर कहना पड़ा कि ताजा घोषणा के बाद उन्हें होम डिलिवरी के लिए बड़ी भारी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं और मौजूदा प्रतिबंधों के चलते इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (ङ्ग्ढ्ढ) के बिग बाजार ने रांची, उत्तराखंड, नोएडा, गाजियाबाद, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, फरीदाबाद, गुजरात और राजस्थान में भी होम डिलिवरी की सर्विस शुरू की है। 1 दिन के लॉकडाउन के लिए सरकार द्वारा जारी अधिकारिक सूचना के अनुसार, राशन की दुकानें (इअए के अंदर आने वाली), फूड, ग्रॉसरी, फल, सब्जियों, डेयरी, मिल्क बूथ, मीट, फिश, पशुआहार से संबंधित दुकानें खुली रह सकती हैं।

बिग बाजार और फूडहॉल जैसे रिटेल नेटवर्क के साथ फ्यूचर रिटेल इस समय 400 से अधिक शहरों में अपने 1,500 स्टोर्स के साथ रिटेल स्पेस के 16 मिलियन वर्ग फुट को कवर करती है।

कोरोना का कहर

जानलेवा वायरस की दवा बनाने में जुटे कई देश, भारत भी कर रहा कोशिश

नई दिल्ली। एजेंसी

किसी भी देश को अब तक नहीं मिली है कामयाबीकोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं वैज्ञानिकअभी वैक्सीन बनने में लग सकता है थोड़ा वक्त दुनियाभर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की अब तक कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है। चीन और अमेरिका समेत भारत भी इसकी वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि आखिर हम कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में अब तक कहां पहुंचे हैं। वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के देशों की अब तक की तैयारी कर रहे हे।

कोरोना से मचा हाहाकार

कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचाया हुआ है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग संक्रमित हैं। तेजी से फैल रही इस महामारी को रोकने के लिए दुनियाभर के वैज्ञानिक लैब में कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन सकी है। इसलिए अभी तक सिर्फ इस वायरस से बचाव ही किया जा सकता है। अभी वैक्सीन आने में करीब सालभर का वक्त लग सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे।

वैक्सीन की खोज में कहां तक पहुंची दुनिया

भारत में जानी मानी कंपनी सिप्ला 6 महीने में कोरोना की दवा पेश कर सकती है। ऐसा हुआ तो ये दवा बनाने वाली सिप्ला भारत की पहली कंपनी होगी। फ्रांस में वैक्सीन बनाने और उससे 6 दिन में संक्रमित इंसान के ठीक होने का दावा किया गया है। मगर उसका टेस्ट अभी बाकी है। अब बात करें चीन की तो एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, लेकिन उसके ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की तलाश है। इसी तरह से अमेरिका ने जर्मनी की फर्म CureVac को अमेरिका में दवा बनाने का न्योता दिया है। कई अमेरिकी वैज्ञानिक भी इस काम में जुटे हैं। जर्मनी में BioNTech कंपनी में वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं।

महामारी का इलाज तलाश रहे हैं हजारों वैज्ञानिक

इसके अलावा दुनियाभर की सैकड़ों निजी लैब्स, हजारों वैज्ञानिक और दवा कंपनियां इस कोशिश में जुटी हुई हैं। ताकि जल्द से जल्द इस महामारी का इलाज ढूंढा जा सके। अभी कोरोना से पीड़ित मरीजों को आइसोलेशन में रखकर उनका हरसंभव इलाज किया जा रहा है। कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है।

भारत में कोरोना के 600 से ज्यादा केस

गौरतलब है कि देशभर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 600 से ज्यादा कंफर्म केस मिले हैं। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 46 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र और केरल प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में 112 और केरल में 105 केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते

केसों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। यह लॉकडाउन बुधवार से लागू हो गया है और 14 अप्रैल तक चलेगा। दफ्तर, बाजार, सार्वजनिक परिवहन सबकुछ बंद है। प्रधानमंत्री ने साफ-साफ कहा है कि इन 21 दिनों तक इस देश में कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। केवल जीवनरक्षक सेवाएं ही इस दौरान जारी रहेंगी।

मंत्रिमंडल ने कपड़ा, मेड अप निर्यात के लिये शुल्क प्रोत्सहन योजना की अवधि बढ़ायी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निर्यात के लिए परिधान और चादर, कालीन जैसे मेड अप उत्पादों की खेप पर केंद्रीय और राज्य स्तरीय करों और शुल्कों का बोझ खत्म करने की योजना की अवधि बढ़ा दी है।परिधान और मेड अप की निर्यात खेप पर राज्य एवं केंद्र स्तरीय कर व शुल्कों की वापसी की यह योजना अब पहली अप्रैल से तब तक जारी रहेगी जब तक कि इसे निर्यात वस्तुओं पर कर और शुल्क वापसी की नयी योजना में समाहित न कर दिया जाए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कपड़ा और मेड अप के निर्यात पर राज्य एवं केंद्रीय करो तथा शुल्कों से छूट की योजना की अवधि एक अप्रैल से आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी गयी है। यह योजना तबतक के लिये बढ़ायी गयी जबतक आरओडीटीईपी अमल में नहीं आती। आरओडीटीईपी निर्यातकों के लिये योजना है जिसके तहत निर्यातक निर्यात वाले वस्तुओं पर जो भी कर देते हैं, उसे वापस ले सकते हैं। उन्हें यह छूट उन करों पर मिलेगी जो मौजूदा योजनाओं या प्रणाली के तहत रिफंड या छूट के दायरे में नहीं आते।

लॉकडाउन के बीच सीओएआई का ग्राहकों से आग्रह

किफायत से करें डाटा का इस्तेमाल ताकि चलती रहें आवश्यक सेवाएं

नई दिल्ली। एजेंसी

मोबाइल दूरसंचार सेवा कंपनियों के संगठन सीओएआई ने बुधवार को मोबाइल उपभोक्ताओं से डेटा नेटवर्क का जिम्मेदारी से उपयोग करने का आग्रह किया ताकि आवश्यक सेवाएं संचार ढांचे पर आसानी से चल सकें। सीओएआई ने जनता से यह अपील ऐसे समय में की है, जब सरकार के कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए उपायों के बाद से पिछले कुछ दिनों में डेटा का उपयोग लगभग 30 प्रतिशत बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों के बंद की घोषणा की। घोषणा के तुरंत बाद केंद्र ने कहा कि इस अवधि के दौरान सभी सड़क, रेल और हवाई सेवाएं निलंबित रहेंगी। कोरोना वायरस से देश में कम से कम नौ लोगों की जान जा चुकी है और 550 से अधिक संक्रमित हैं। भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर संघ के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने कहा कि 'हम लोगों से जिम्मेदारी के साथ नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं... इंटरनेट और नेटवर्क के किसी भी गैर-जरूरी उपयोग से बचने के लिए... दूरदराज में चल रहे काम, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, भुगतान और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से चल सकें।' उन्होंने कहा कि मोबाइल उपयोगकर्ता व्यस्त समय के अलावा सुबह या देर शाम को ऑनलाइन गतिविधियां कर सकते हैं। मैथ्यूज ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में डेटा मांग में 20-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बंद लागू करने और सामाजिक दूरी बनाने के चलते यह मांग बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी कंपनियां वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के लिए अपने प्लेटफार्मों पर वीडियो के लिए बिट दर कम कर रही हैं।

रिलायंस के शेयर में आई जोरदार तेजी, 14 फीसदी बढ़कर 1081 रुपये पर बंद

नई दिल्ली। बुधवार के दिन देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिली है। NSE पर कंपनी का शेयर 14.65 फीसदी यानी 138 रुपये बढ़कर 1081 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। सेसेक्स-निफ्टी में तेजी में प्रमुख योगदान रिलायंस के शेयर का ही रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर तिमाही में आरआईएल का मुनाफा 11784 करोड़ रुपये का रहा था, जो रिकॉर्ड मुनाफा है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल सेल्स 1.52 लाख करोड़ रुपये रही। 11 साल की सबसे बड़ी तेजी-BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1862 अंक बढ़कर 28536 पर बंद। वहीं, NSE का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 517 अंक बढ़कर 8,318 पर बंद। 2009 के बाद बाजार में सबसे बड़ी INTRA-DAY तेजी देखने को मिली। कोरोना वायरस की वजह से शेयर बाजार में आई गिरावट के चलते रिलासं इंडस्ट्री के शेयर पर भी दबाव दिखा था।

लॉकडाउन के बीच अपने लिए 'जरूरी सेवा' कैटिगरी मांग रहीं ये कंपनियां

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की बड़ी फूड और बेवरेज कंपनियों ने सरकार से अपने लिए 'जरूरी सेवा' की कैटिगरी मांगी है जिससे दुकानों पर इन प्रॉडक्ट्स की कमी और उपभोक्ताओं के बीच अफरातफरी की स्थिति से बचा जा सके। ब्रिटानिया, पारले, पेप्सिको, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला और ध्रुव सहित कई कंपनियों ने मंगलवार को सरकार को इंडस्ट्री के तीन अलग संगठनों के जरिए पत्र लिखकर यह मांग की है।

इनमें से एक पत्र में कहा गया है, 'केंद्र और राज्य सरकारें प्रतिदिन के आधार पर कई अडवाइजरी और नोटिफिकेशंस जारी कर रही हैं। स्थानीय प्रशासन फैक्ट्रियों के शटडाउन को लागू कर रहे हैं और इससे मुश्किलें बढ़ रही हैं।' कन्ज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को ये पत्र फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री (FICCI), ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स असोसिएशन (AIFPA) और ऊए इंडिया स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) की ओर से लिखे गए हैं।

USISPF में ITC, डेलॉयट, अडोबी सिस्टम्स और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां शामिल हैं। कन्ज्यूमर अफेयर्स सेक्रटरी पवन अग्रवाल को लिखे एक अन्य पत्र में USISPF ने कहा है, 'फूड प्रॉडक्ट्स की सप्लाई चेन बहुत इंटीग्रेटेड है और इसके एक हिस्से में रुकावट आने का कृषि क्षेत्र पर बड़ा असर होगा।' कंपनियों का कहना है कि उन्होंने सभी प्लांट्स में विजिटर्स का प्रवेश रोक दिया है, वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हाइजीन की स्थितियों की निगरानी की जा रही है और फैक्टरी परिसरों में सेनिटाइजेशन किया जा रहा है। कंपनियों ने जरूरी और गैर-जरूरी वस्तुओं के बीच संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया के साथ ही नियमों को लागू कराने को लेकर सरकारी अधिकारियों को स्पष्ट दिशानिर्देश देने की मांग की है। पत्र में कहा गया है, 'नियमित सप्लाई को बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है कि इस सेक्टर को कामकाज और मूवमेंट की किन्हीं बंदिशों के तहत न रखा जाए। फूड और बेवरेज सेक्टर के साथ ही फूड इन्ग्रीडिएंट्स कंपनियों को भी बिना किसी रुकावट के ऑपरेट करने की अनुमति होनी चाहिए।'

पत्र में बताया गया है कि बहुत सी कंपनियों को स्थानीय प्रशासन की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनसे कामकाज रोकने के लिए कहा जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि इन बंदिशों का कृषि उत्पादन और किसानों पर सीधा असर पड़ेगा। फूड और बेवरेज सेक्टर लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये या देश की इश्ण्ड इंडस्ट्री का लगभग 55 पर्सेंट होने का अनुमान है। कोरोना वायरस के संकट की वजह से केवल जरूरी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है और इससे इकॉनमी की रफ्तार थम गई है।

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का एलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसका देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा पड़ेगा। अब जानकारों ने अनुमान लगा लिया है कि इन 21 दिनों के भीतर देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा।

9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान संभव

आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्थिक जगत के जानकारों के मुताबिक 21 दिनों के लॉकडाउन में देश को 120 अरब डॉलर यानी करीब 9.12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ सकता है। देश के एक मशहूर बिजनेस चैनल पर भी आर्थिक जानकारों ने इस बात की संभावना व्यक्त की है।

देश की तरक्की की रफ्तार होगी धीमी

जीडीपी के आधार पर इसे देखें तो माना जा सकता है इतने नुकसान के बाद कुल जीडीपी के 4 फीसदी तक पर इसका असर देखा जा सकता है। दरअसल लॉकडाउन के चलते देश में औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, परिवहन सेवाओं पर रोक लग गई है और सरकारों के राजस्व के सभी मोर्चों पर एक्टिविटीज रुक गई हैं। इसके चलते साफ है कि देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बेहद धीमी हो जाएगी।

लॉकडाउन-कर्फ्यू का होगा गहरा असर

बता दें कि लॉकडाउन से पहले ही कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी में तेज गिरावट आने का अनुमान दिया हुआ है और अब तो आईएमएफ ने भी साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस के चलते वैश्विक मंदी आ सकती है और ये 2009 के ग्लोबल आर्थिक संकट से भी गहरा होगा।

वित्तीय घाटा भी बढ़ेगा

आर्थिक जानकारों ने ये भी कहा है कि सरकार वित्तीय घाटे के तय लक्ष्य को पार कर सकती है। सरकार ने 2021 के लिए वित्तीय घाटा 3.5 फीसदी पर रहने का अनुमान दिया था लेकिन ब्रिटिश ब्रोकरेज हाउस बार्कलेज ने अनुमान दिया है कि ये 5 फीसदी पर आ सकता है।

बार्कलेज का अनुमान

बार्कलेज ने ये भी कहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीतिगत दरों में कटौती कर सकता है जिसकी वजह से राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में सरकार को दिक्कत हो सकती है। बता दें कि आने वाली 3 अप्रैल को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है जिसके लिए साफ माना जा रहा है कि इसमें आरबीआई रेपो रेट में अच्छी खासी कटौती कर सकता है। ये शुरुआत में 0.65 फीसदी हो सकती है और आगे चलकर आरबीआई रेपो रेट में 1 फीसदी तक की कटौती भी कर सकता है।

कोरोना वायरस

लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हो सकता है नौ लाख करोड़ रुपये का नुकसान

मुंबई। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये देश भर में की गयी बंदी (लॉकडाउन) से अर्थव्यवस्था को 120 अरब डॉलर (करीब नौ लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हो सकता है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के चार प्रतिशत के बराबर है। उन्होंने राहत पैकेज की जरूरत पर जोर देते हुए बुधवार को आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में भी कटौती की। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक तीन अप्रैल को अगली द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के निष्कर्षों की घोषणा करने वाला है। विश्लेषकों का अनुमान है कि रिजर्व बैंक नीतिगत दर में बड़ी कटौती करेगा। यह भी मानकर चलना चाहिये कि राजकोषीय घाटा का लक्ष्य अब पार हो जाना तय है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिये तीन सप्ताह के लिये राष्ट्रव्यापी बंदी की घोषणा की है। शोध-सलाह कंपनी बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये वृद्धि दर के अनुमान में 1.7 प्रतिशत की कटौती कर इसके 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उसने कहा, ''हमारा अनुमान है कि राष्ट्रव्यापी बंदी की कीमत करीब 120 अरब डॉलर यानी जीडीपी के चार प्रतिशत के बराबर रह सकती है।'' कंपनी ने कहा कि केंद्र सरकार की तीन सप्ताह की बंदी से ही 90 अरब डॉलर का नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र जैसे कई राज्य पहले ही बंदी कर चुके हैं, उससे भी नुकसान होगा। बार्कलेज ने यह भी कहा कि अप्रैल में रिजर्व बैंक रेपो दर में 0.65 प्रतिशत की कटौती करेगा तथा अगले एक साल में इसमें एक और प्रतिशत की कटौती की जाएगी। घरेलू शोध-सलाह कंपनी एमके ने अन्य देशों की तुलना में शीघ्रता से कदम उठाने को लेकर सरकार को बधाई देते हुए कहा कि इससे होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिये उपाय नहीं किये गये हैं। उसने कहा, ''सरकार बंदी के आर्थिक असर को लेकर अभी तक चुप ही रही है, असर को कम करने के उपायों को तो छोड़ ही दीजिये।'' कंपनी ने कहा कि नोटबंदी तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दोहरी मार झेलने वाले असंगठित क्षेत्र पर इसका सर्वाधिक असर होगा। उसने छोटी कंपनियों को सस्ता कर्ज देने, कर्ज का पुनर्गठन करने तथा नकदी हस्तांतरण को सरकार के पैकेज के संभावित उपाय बताया।

पैनिक होकर सामान न खरीदें, 21 दिन खुली रहेंगी दुकानें

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन है। घबराहट में लोग सामान खरीदकर अपने घरों में भर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में परेशानी न हो। इसी बीच कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार तीन महीने का राशन अडवांस में देगी। देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा। किसी जरूरी सामान की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है की लॉकडाउन की विस्तारित अवधि में देशभर में कहीं भी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बंद नहीं होंगी। लोग घबराकर सामानों की खरीदारी नहीं करें, नहीं तो इससे जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यक सेवाओं की सभी दुकानें हर रोज खुलेंगी, चाहे दूध हो, फल-सब्जी हो, अंडा-मांस हो या फिर अन्य जरूरी सामान। सभी वस्तुएं वैसे ही उपलब्ध होंगी, जैसे आम दिनों में उपलब्ध होती है। उन्होंने गुजरात के एक शहर और पुडुचेरी की एक दुकान का फोटो दिखाकर कहा कि लोग जागरूक हों। दुकान में खरीदारी करते वक्त भी उचित दूरी बनाकर रखें। इससे वह सामान भी ले पाएंगे और संक्रमण से भी बचे रहेंगे। कुछ सामानों की कालाबाजारी से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार इस तरह का काम करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी।उन्होंने लोगों से अपील की कि यह संकट की घड़ी है, एक दूसरे का साथ दें। जमाखोरी ना करें नहीं तो मजबूरन सरकार को कार्रवाई करनी होगी। जावड़ेकर ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया सरकार 27 रुपये कीमत का गेहूं 2 रुपये में देती है और हम राज्यों को अडवांस में जरूरी सामान भेज रहे हैं।

Coronavirus: Global Airlines

उद्योग को साल 2019 के मुकाबले हो सकता है 44% राजस्व का नुकसान: IATA

नई दिल्ली। एजेंसी

द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान का आकलन प्रस्तुत किया है। कोरोना वायरस के चलते इससे पीड़ित कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। इसके चलते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें बंद कर दी गई हैं। इन यात्रा प्रतिबंधों और वैश्विक मंदी की आशंका के चलते आईएटीए का अनुमान है कि इंडस्ट्री का पैसेंजर रेवन्यू साल 2019 के आंकड़े से 44 फीसद या 252 बिलियन डॉलर कम रह सकता है। इससे पहले आईएटीए ने पांच मार्च को इंडस्ट्री को 113 बिलियन डॉलर का राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया था। उस समय दुनिया में कई देशों ने कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, इससे अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रैवल मार्केट पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। आईएटीए के महानिदेशक और सीईओ Alexandre de Juniac ने कहा, 'एयरलाइन इंडस्ट्री अपने सबसे बुरे दौर का सामना कर रही है। सिर्फ कुछ सप्ताहों में ही हमारा पिछली सबसे बुरी स्थिति मौदूदा अनुमान के सामने अच्छी प्रतीत होने लगी है।' उन्होंने एक स्टेटमेंट में आगे कहा, 'बिना किसी तात्कालिक सरकारी मदद के कोई भी इंडस्ट्री खड़ी नहीं रहेगी। एयरलाइन्स को इससे उबरने के लिए तत्काल 200 बिलियन डॉलर के लिक्विडिटी सपोर्ट की आवश्यक है।' उन्होंने कहा कि कुछ सरकारों ने इसके लिए आगे आना भी शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत अधिक को इसका अनुसरण करने की जरूरत है। इस आकलन के अनुसार, पूरे साल की पैसेंजर डिमांड (रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स या RPKs) साल 2019 के मुकाबले 38 फीसद घट गई है। आईएटीए 290 एयरलाइन्स का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि वैश्विक एयर ट्रैफिक का 82 फीसद है।

यह मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि देवी से ही उत्पन्न हुई है और देवी ही विभिन्न रूपों में इस सृष्टि में दृश्यमान हैं। नवरात्रि उन्हीं की आराधना का पर्व है। यह जीवन में नवीन ऊर्जा व नवीन संकल्प का प्रतीक है और स्वयं को पवित्र कर जीवन में संतुलन लाने का एक महान अवसर है।

इलस्ट्रेशन: सुदर्शन मल्लिक

चेतना को शुद्ध और पवित्र करती है देवी शक्ति

नवरात्रि पर विशेष

श्री श्री रविशंकर

नवरात्रि की नौ रात्रियां अत्यंत अनमोल होती हैं और वे सूक्ष्म ऊर्जा से समृद्ध होती हैं। इन नौ दिनों के दौरान देवी शक्ति के नौ रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है।

नवरात्रि के पहले तीन दिन महादुर्गा के रूप होते हैं, जो वीरता, आत्मविश्वास और तमोगुण की अधिष्ठाता का प्रतीक हैं। नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे-तीन दिन महालक्ष्मी के रूप होते हैं, जो धन और रजोगुण की अधिष्ठाता का प्रतीक हैं। नवरात्रि के आखिरी तीन दिन महासरस्वती का रूप हैं, जो ज्ञान और सत्व गुण की अधिष्ठाता का प्रतीक हैं। ये तीन मुख्य गुण हमारे विशाल ब्रह्माण्ड की स्त्री शक्ति माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा-अर्चना करने से हम इन तीन गुणों में सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे वातावरण में सत्व की वृद्धि होती है।

नवरात्रि जड़ता और नकारात्मक प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने का समय है, जिसे देवी द्वारा बैल का वध करने के रूप में सुंदरता से दर्शाया जाता है। जो सुस्त, असंवेदनशील और जड़तापूर्ण होता है, हम उसे क्या कहते हैं? एक बैल! सिर्फ देवी मां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त ऊर्जा से ही इस बैल का विनाश कर सकती हैं। जैसे एक शिशु को जन्म लेने में नौ महीने लगते हैं, वैसे ही देवी नौ दिनों के विश्राम के उपरांत दसवें दिन भक्ति और पवित्र प्रेम के रूप में प्रकट होती हैं। उस पवित्रता और भक्ति से देवी ने सुस्ती और जड़ता वाले बैल पर विजय प्राप्त की।

शांति और व्यवस्था को स्थापित करने के लिये देवी ने प्रकट होकर कैसे असुरों का वध किया, इस संबंध में अनेक कथाएं हैं। ये असुर नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक होते हैं, जो कभी भी किसी पर हावी हो सकते हैं। नवरात्रि आत्मा या प्राण का उत्सव है, जो स्वयं ही असुरों का विनाश कर सकता है। जब आप उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, तो कोई भी असुर आप के पास नहीं आएगा और वे लुप्त हो जाएंगे। किसी समय देवताओं ने देवी मां से कहा कि 'आप को प्रकट होकर इनसे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? आपकी सिर्फ एक हुंकार से ही सारे राक्षसों का विनाश हो जाएगा और वे भस्म हो जाएंगे। परन्तु हमें पता है कि आप युद्ध इसलिए करती हैं, जिससे वह क्रीड़ापूर्ण और रंगमय हो जाए और संसार अत्यंत रोचक बन जाए। इसलिए आप आकर त्रिशूल, गदा और चक्र से क्रीड़ा करती हैं। और इन अस्त्रों से असुर भी शुद्ध हो जाते हैं और आपको प्राप्त करते हैं।' यह सिर्फ एक ही प्रकाश और चेतना है, जो स्वयं में वापसी के लिए दो भूमिका निभाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई दो भिन्न शक्तियां नहीं होतीं। सिर्फ एक ही शक्ति होती है, जिसके दो रूप होते हैं। देव और असुर अलग अलग रूप में आते हैं, फिर एक ही रूप में विलीन हो जाते हैं।

> नवरात्रि आत्मा या प्राण का उत्सव है, जो स्वयं ही असुरों का विनाश कर सकता है। जब आप उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, तो कोई भी असुर आप के पास नहीं आएगा और वे लुप्त हो जाएंगे।

देवी मां को सिर्फ बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ के रूप में ही नहीं, बल्कि भ्रांति के रूप में भी पहचाना जाता है। वे सिर्फ प्रचुरता या लक्ष्मी ही नहीं, परन्तु भूख या क्षुधा और तृष्णा भी हैं। सारे ब्रह्माण्ड में देवी मां के इस स्वरूप की पहचान होने से कोई ध्यान की गहन अवस्था में जा सकता है। देवी मां वह नहीं हैं, जो सिर्फ हाथ में बड़ा त्रिशूल धारण किये हुए हैं। वह ऊर्जा का एक स्वरूप हैं और दिव्यता की अभिव्यक्ति हैं। देवी मां या पवित्र चेतना ही सभी रूपों में व्याप्त है, जिसके अलग अलग नाम हैं। इस पवित्र आत्मा के विविध स्वरूप का आह्वान नवरात्रि के दौरान किया जाता है। जैसे आप गर्भ में नौ महीने बिताए, इन नौ दिनों को स्वयं के साथ व्यतीत करें और एक नई शुद्ध चेतना का सृजन करें। फिर सारे बुरे कर्म, स्मृतियां और संस्कार निर्मल होकर पवित्र हो जाएंगे।

देवी शक्ति व्यक्ति की चेतना को शुद्ध और पवित्र करती है और फिर सार्वभौमिक चेतना और सृष्टि भी पवित्र और शुद्ध हो जाती है। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद हम उत्सव मनाते हैं। दसवां दिन-विजय का दिन। इस दिन बुरी शक्तियों पर देवी मां की विजय का उत्सव मनाया जाता है।

यह हमारी दिव्य चेतना की पराकाष्ठा के जागरण का दिन है। जो कुछ भी आप को प्राप्त हुआ है, उसके लिए कृतज्ञता और सम्मान की अनुभूति करें।

श्री दुर्गा सप्तशती महिमा

सबका कल्याण करता है 'त्रिपुंज'

श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय के 700 श्लोकों का नवरात्रि के प्रत्येक दिन में पाठ किए जाने का विधान है, लेकिन आज के व्यस्ततापूर्ण समय में अगर समयाभाव के कारण 13 अध्याय संभव नहीं हों, तो कीलकम्, कवचम् व अर्गला के साथ चौथे व ग्यारहवें अध्याय का पाठ लाभकारी है। श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र में अर्गला व कीलकम् के साथ दूसरे, तीसरे व चौथे अध्याय का पाठ उपयोगी है।

श्री दुर्गा सप्तशती का कवचम् सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। 'ऊं नमः चण्डिकायै' से प्रारम्भ हुए इस महामंत्र निधि में देवी के नौ नाम हैं और इसमें कुल 55 श्लोक हैं। इसमें देवी के रूप, स्वरूप व वाहन के साथ यश और कृति के वृत्तान्त का अपूर्व वर्णन है। अर्गला स्तोत्रम् का श्रीगणेश भी 'ऊं नमः चण्डिकायै' से ही होता है, जिसमें महामाया से 18 बार अनुनय-विनय की गई है कि 'हे माता! आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो।' श्री दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी अर्गला स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। इसमें प्रारंभ में देवी के एकादश नाम सहित कुल 25 श्लोक हैं।

कीलक स्तोत्रम का प्रारम्भ भी 'ऊं नमः चण्डिकायै' से हुआ है, जिसमें कुल 142 श्लोकों से भगवती के समक्ष आत्म निवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्णन है कि कीलकम् जैसे कल्याणमय स्तोत्र का हमेशा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का उच्च स्वर

से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। 'देवी सूक्त' भी मंगलकारी है, जिसमें 'नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोः नमः' मंत्र का समावेश है। कहते हैं कि जिस घर में श्री दुर्गा सप्तशती रहती है, वहां मां दुर्गा किसी न किसी रूप में अवश्य रहती हैं। कीलकम्, कवचम् व अर्गला को 'त्रिपुंज' कहा जाता है, जो देवी को अत्यंत प्रिय है। पहले कवचम् फिर अर्गला और अंत में कीलकम् का पाठ शास्त्रसम्मत बताया गया है। इसके साथ ही देवी के 32 नामों की माला, जैसे 'अथ दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला' भी परमकल्याणकारी है। विवरण है कि जो भी दुर्गा सप्तशती में अंकित कीलकम् स्त्रोत, कवचम् स्त्रोत व अर्गला स्तोत्रम का पाठ करता है, जगन्माता उसके सम्पूर्ण पंचकार्य, जैसे- तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहृति और अनुग्रह का निष्पादन स्वयं कर आगे का हर मार्ग सर्वसुलभ कर देती हैं।

डॉ. राकेश कुमार सिन्हा 'रवि'

देवी महात्म्य

भ्रमजाल का नाश करती हैं जग जननी

नन्दकिशोर श्रीमाली

'या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता।'

हम सब शक्तिपुंज हैं, परंतु हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि हमें शक्ति की महानता का आभास नहीं होता है, क्योंकि हम अप्रत्यक्ष को देख नहीं पाते हैं। यह भ्रम जाल सर्वव्यापक है और इस जाल का आश्रय लेकर शक्ति इस जगत का कार्य व्यापार नियंत्रित करती है। इस भ्रमजाल के परे जाने की क्रिया सत्य दर्शन है।

दुर्गा सप्तशती उस भ्रम जाल के परे ले जाने वाला ग्रंथ है, यहां कथा राजा सुरथ और वैश्य समाधि के माध्यम से कही गई है, जो अपना-अपना घर परिवार छोड़कर वन में मेधा ऋषि से देवी की महिमा जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। उन्हें शक्ति के विविध रूपों का बारह अध्यायों के माध्यम से कथा एवं महिमा का ज्ञान दिया गया है। तेरहवें अध्याय में समाधि वैश्य और राजा सुरथ ने शक्ति की प्रसन्नता हेतु तीन वर्षों तक उनकी आराधना की। उनकी घोर तपस्या से शक्ति प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती हैं।

यहां पर शक्ति पुनः संकेत में बात कर रही हैं। मेधा उच्च कोटि की बुद्धि है, जो

प्रत्येक जीव में है। यह बुद्धि हर मनुष्य में शक्ति का हस्ताक्षर है। विज्ञान इसे अंतर्ज्ञान कहता है, तो कई बार यह 'सामान्य ज्ञान' भी कहा गया है, अर्थात परिस्थितियों को निष्पक्षता से देखने की शक्ति।

राजा सुरथ व्यक्ति के भीतर निहित मन है। इन्द्रियों द्वारा चालित इस शरीर रूपी रथ को सही दिशा में ले जाने का उत्तरदायित्व मन का है, पर यह मन काबू में ही नही रहता है और समाधि वैश्य का रहस्य अति रोचक है।

वैश्य समुदाय धनोपार्जन में जुटा रहता है और समाधि शब्द का अर्थ ज्ञान प्राप्ति का चरमोत्कर्ष है। ज्ञान 'सुदर्शन' के अतिरिक्त इस जीवन में और कुछ नहीं है। धन-उपार्जन में दिन-रात जुटे हुए सांकेतिक रूप से परतंत्र लोगों को चैतन्य कर शक्ति समाधि यानि परम ज्ञान की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है।

दुविधा यह है कि सुरथ और समाधि सत्य नहीं देख पा रहे है। उनके जीवन में मोह रूपी भ्रम की अधिकता है, जिस कारण वे प्रेम, कर्त्तव्य और स्वार्थ के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। अपने ही सगे-सम्बन्धियों द्वारा छले जाते हैं, उनके द्वारा त्याग दिए जाते हैं और फिर भी उन्हीं के लिए बेचैन रहते हैं।

हम जीवन से अधिक धन को महत्व देते हैं। अपने परिवारजनों के लिए धन संचित करते हैं और फिर धन हीनता की स्थिति में उन्हीं परिवारजनों द्वारा तिरस्कृत होते हैं। जीवन की इस विचित्र विडंबना का हल शक्ति करती है, भ्रमजाल के व्यूह का नाश करके, जिस प्रकार उन्होंने सुरथ और समाधि के लिए किया। भ्रम जाल के नष्ट होने के बाद मनुष्य अपने मन को अपनी बुद्धि के हिसाब से आध्यात्मिक या भौतिक सफलता की ओर मोड़ देता है।

BS6 इंजन के साथ Maruti Suzuki Tour S CNG वेरिएंट में हुई लॉन्च, जानें कीमत

नई दिल्ली। एजेंसी

Maruti Suzuki ने देश में अपनी BS6 मानकों के अनुरूप कॉम्पैक्ट सेडान Tour S CNG को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 5.80 लाख रुपये रखी है, जो कि ए (O) CNG ट्रिम 6.40 लाख रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) तक जाती है। Maruti Suzuki Tour S CNG भारतीय बाजार में Swift DZire का पुराना जनरेशन मॉडल है और इसे सिर्फ फ्लीट बाजार (टैक्सी) के लिए बेचा जाता है। नए पावरट्रेन के साथ इसे तीन वेरिएंट्स - ए CNG, ए (O) Petrol और ए (O) CNG में उतारा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Xcent और Ford Aspire के फ्लीट वेरिएंट्स से है।

Maruti Suzuki Tour S में कंपनी ने समान 1.2 लीटर के-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया है जो अब BS6 मानकों के अनुरूप अपडेट कर दिया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पुराना 1.2 लीटर इंजन ही है जो Dzire में मिलता है, ना कि फेसलिफ्ट मॉडल में मिलने वाला 1.2 लीटर डुअल-VVT इंजन। CNG विकल्प के साथ इसके माइलेज में भी सुधार देखने को मिलेगा।

मारुति सुजुकी टूर एस मूल रूप से पुरानी जनरेशन के Dzire पर आधारित नो-फ्रिल्स वर्जन है। इस मॉडल पर ऑल-व्हाइट पेंट स्कीम के साथ स्टील व्हील्स, ब्लैक्ड-आउट ग्रिल और बॉडी-कलर्ड बंपर्स दिए गए हैं। केबिन में कंपनी ने आवश्यक चीजों के तौर पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए HVAC यूनिट, पावर स्टीयरिंग और पावर विंडो दिया है। इसके अलावा ड्राइवर एयरबैग, ABS, सीटबेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर और हाई-स्पीड अलर्ट सहित अनिवार्य सुरक्षा सुविधाएं भी दी गई हैं।

इस महीने की शुरुआत में मारुति सुजुकी ने घोषणा की थी कि वह डीलरशिप्स के कमर्शियल नेटवर्क का विस्तार करेगी और इसमें Tour रेंज को शामिल करेगी। Tour रेंज में Super Carry LCV, Tour H1 (Alto), Tour H2 (Celerio), Tour S (Dzire), Tour V (Eeco) और Tour M (Ertiga) शामिल हैं। देशभर में कार निर्माता कंपनी के पास 234 से ज्यादा शहरों में 320 कमर्शियल वाहनों के आउटलेट्स मौजूद हैं।

वालमार्ट इंडिया ने किया ऐलान

समीर अग्रवाल होंगे बेस्ट प्राइस के सीईओ

मुंबई। एजेंसी

वालमार्ट इंडिया ने घोषणा की है कि समीर अग्रवाल को पदोन्नति देकर बेस्ट प्राइस का चीफ एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है। वह 1 अप्रैल से कार्यभार संभालेंगे। वह सीधे डर्क वान डेन बेर्घे को रिपोर्ट करेंगे, जो एशिया व ग्लोबल सोर्सिंग के रीजनल सीईओ और एक्ज़ीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। अग्रवाल, कृष अय्यर से सीईओ का पद ले रहे हैं जो पूर्णकालिक प्रबंधन से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं और अब बेस्ट प्राइस, वालमार्ट इंडिया के सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। वह आठ वर्षों तक कंपनी के साथ सफलतापूर्वक जुड़े रहे हैं। डर्क वान डेन बेर्घे ने कहा, 'सैम ने बीते दो वर्षों में बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने हमारी पेशकश को ज्यादा उपभोक्ता केन्द्रित बनाने तथा हमारी भावी ओमनी चैनल सेवाओं हेतु डिजिटल पेशकश विकसित करने की जिम्मेदारी निभाई। पेचीदा स्थितियों को समझने की उनमें खास काबिलियत है तथा कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाने में वह निर्णायक कदम उठाने में सक्षम हैं। वह एक मजबूत लीडर हैं जिनमें सेवा, आदर, उत्कृष्टता व ईमानदारी के वही मूल्य हैं जिनके लिए वालमार्ट को जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं पूरे भारत में फैले हमारे बैस्ट प्राइस सदस्यों और ऐसोसिएट्स के लिए वह सकारात्मक प्रभावकारी सिद्ध होंगे।' अग्रवाल अप्रैल 2018 में एक्ज़ीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वालमार्ट इंडिया से जुड़े, उन्होंने रणनीति एवं प्रशासन का काम संभाला तथा जनवरी 2020 में पदोन्नति प्राप्त कर वह डिप्टी सीईओ बने।

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 1340 करोड़ रुपये की पूंजी डाले जाने को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। एजेंसी

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने बुधवार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में 1,340 करोड़ रुपये की पूंजी डाले जाने की योजना को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी डाले जाने से उनके दिए गए कार्जों (उनकी सम्पत्ति) पर भारांकित जोखिम की तुलना में उनका पूंजी आधार सुधरेगा। आआरबी को दी जाने वाली इस पूंजी के लिए केंद्र सरकार 670 करोड़ रुपये देगी और इनके प्रवर्तक बैंक इतनी ही राशि उपलब्ध कराएंगे।

मजबूत मांग के कारण ग्वारगम वायदा कीमतों में 3.99 प्रतिशत की तेजी

नयी दिल्ली। एजेंसी

हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को ग्वारगम की कीमत 191 रुपये की तेजी के साथ 4,972 रुपये प्रति पांच क्विन्टल हो गयी। एनसीडीईएक्स में ग्वारगम के अप्रैल माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 191 रुपये अथवा 3.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,972 रुपये प्रति पांच क्विन्टल हो गयी जिसमें 31,930 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी प्रकार, ग्वारगम के मई माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 193 रुपये या 3.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,034 रुपये प्रति पांच क्विन्टल हो गयी जिसमें 17,985 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि हाजिर बाजार में मजबूती के रुख को देखने के बाद व्यापारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे मुख्यतः यहां ग्वारगम वायदा कीमतों में तेजी आई।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने ली बैठक

नई दिल्ली। एजेंसी

देशभर में लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को यहां एक विशेष बैठक की। इसमें खुदरा दुकानदारों के प्रतिनिधि, ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि और संगठित रिटेल कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। साथ ही, इसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले डीपीआईआईटी के सचिव गुरू प्रसाद महापात्र, औषधि विभाग के सचिव अनिल अग्रवाल और तीनों मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

इस दौरान गृह सचिव अजय भल्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही बेरोकटोक होती रहेगी।

गृह सचिव ने बैठक में उठाई गई चिंताओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों और आम लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी देगी।

इस दौरान तीनों मंत्रालय के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी छोटी-छोटी गड़बड़ियां दूर की जाएंगी और लोगों को हो रही समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों ने आगाह किया कि आवश्यक कदम ऐसे तरीके से उठाए जाएंगे, जो देश में घातक कोविड-19 वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को कम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश एक बेहद गम्भीर चरण से गुज़र रहा है। इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। इस बैठक के शामिल कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने बैठक में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, निर्माता से थोक व्यापारी, थोक विक्रेताओं से खुदरा विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से ग्राहकों को आपूर्ति का मुद्दा उठाया है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं के कारोबार में लगे कारोबारियों की सुरक्षा और किसी भी संभावित उत्पीड़न को रोकने का भी मसला उठाया।

राष्ट्रव्यापी बंदी के दौरान पूंजी, ऋण बाजार की सेवाएं देने वाली संस्थाएं चालू रहेंगी : सेबी

नयी दिल्ली। एजेंसी

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिनों की देशव्यापी बंदी के दौरान पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं चालू रहेंगी। सेबी ने गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा, 'यह आदेश... कहता है कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं को बंदी से छूट दी जाएगी।' सेबी ने मंगलवार रात एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रव्यापी बंदी से छूट पाने वाली संस्थाएं हैं- शेयर बाजार, समाशोधन (क्लीयरिंग) निगम, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, शेयर ब्रोकर, कारोबारी सदस्य, समाशोधन सदस्य, डिपॉजिटरी प्रतिभागी, पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट। सेबी ने कहा है कि इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ऋणपत्र न्यासी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, वैकल्पिक निवेश फंड, निवेश सलाहकार और अन्य सेबी पंजीकृत इकाइयां भी चालू रहेंगी। इसके साथ ही सेबी ने कहा है कि उसके सभी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।

ICU में है इकनॉमी, कोमा से बचाने की जरूरत: HDFC बैंक

मुंबई। एजेंसी

HDFC बैंक के चीफ एग्जिक्यूटिव आदित्य पुरी का कहना है कि इंडियन इकनॉमी आईसीयू में पहुंच गई है और उसको कोमा में जाने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक और सरकार, दोनों को आपात उपाय करने चाहिए। पुरी ने कहा कि उनके बैंक की सेहत काफी अच्छी है और अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो में बैड लोन तेजी से बढ़ने के आसार को लेकर बस कयासबाजी हो रही है। पुरी का कहना है कि उनके बैंक का एक्सपोजर सिर्फ टॉप रेटिंग वाली कंपनियों में है, जो मुसीबत का मौजूदा दौर आसानी से झेल सकती हैं। पुरी ने कहा, 'मेरे हिसाब से एसेट क्लासिफिकेशन के मामले में रिजर्व बैंक के पास कोई विकल्प नहीं है। राहत पैकेज के मोर्चे पर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं है। रिजर्व बैंक को समूची इंडस्ट्री के लिए सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए और सरकार को अपनी आमदनी और खर्च के मोर्चे पर भी आराम से कदम उठाने की जरूरत है।' बेंचमार्क इंडेक्स कई साल के निचले स्तर पर आ गए हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पर गिरावट की गहरी मार पड़ी है। प्राइवेट बैंकों के निफ्टी इंडेक्स ने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडरपरफॉर्म किया है। निवेशकों को डर है कि कोरोना के चलते ऑफिस और फैक्टरी बंद होने से कंपनियों की इनकम घटेगी और उसकी वजह से जॉब लॉस की स्थिति बनेगी। ऐसा होने पर प्राइवेट बैंकों के रिपेमेंट पर चोट पहुंचेगी। इंडियन स्टॉक मार्केट का गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाने वाले प्ब्इण बैंक का शेयर सोमवार को 13% की तेज गिरावट के साथ रू. 770.50 रुपये पर बंद हुआ था। पीक से 40% से ज्यादा नीचे आ चुके बैंक का शेयर मंगलवार को 0.66% की गिरावट के साथ 765.45 रुपये पर बंद हुआ।

ब्रोकरेज फर्म सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन के एनालिस्ट गौतम छुगानी कहते हैं, 'कोरोना वायरस के चलते मार्केट में जो अफरातफरी का माहौल है उसमें प्ब्इण बैंक को अलग तरह के रिस्क और प्रबंधन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एचडीएफसी बैंक के पोर्टफोलियो से दूसरे प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट रिस्क जुड़ा हुआ है। कमजोर इनफॉर्मल इनकम वाले सेगमेंट पर फोकस होने के चलते एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी प्ब्ँ फाइनेंशियल सर्विसेज को भी मौजूदा हालात में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।' पुरी के मुताबिक कोरोना वायरस से उनके बैंक के लोन की क्वॉलिटी पर पड़ने वाले असर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक की एसएमई बुक को एडिशनल कोलैटरल का सपोर्ट है जबकि अनसिक्योर्ड लोन में ज्यादा एक्सपोजर ए और उससे ऊंची रेटिंग वाली कंपनियों के नौकरीपेशा लोगों का है। जब तक लोन बुक इनवेस्टमेंट ग्रेड में है, हमें राहत है। इनमें से ज्यादातर कंपनियों में छह महीने से लेकर एक साल तक हालात को संभालने की क्षमता है। फंडामेंटल बेसिस पर उनकी मजबूत फाइनेंशियल पोजिशन को देखते हुए हम उनकी उनकी कैश फ्लो की समस्याओं का समाधान करने को तैयार हैं।'

कोरोना वायरस: दुनियाभर में अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस से उबारने के प्रयास तेज

लंदन। एजेंसी

दुनियाभर की सरकारें और केन्द्रीय बैंक इन दिनों अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कोरोना वायरस के गंभीर प्रभाव से बचाने के लिये अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। दुनियाभर के केन्द्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिये नई मुद्राओं का प्रकाशन, भारी व्यय करना, बड़े पैमाने पर रिण की गारंटी देना, कर रियायत देने और कर्मचारियों कामगारों को सीधे भुगतान जैसे कई कदम उठाये जा रहे हैं। एएफपी ने इस संबंध में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड- 19 के मद्देनजर उठाये जा रहे कदमों का सर्वेक्षण किया। कोविड- 19 चीन के वुहान से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। इससे दुनिया में मंदी गहराने का खतरा पैदा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में सीनेट नेताओं और व्हाइट हाउस के बीच बुधवार को अर्थव्यवस्था को 2,000 अरब डालर का प्रोत्साहन पैकेज दिये जाने के प्राधान वाले विधेयक पर सहमति बन गई। सीनेट के नेताओं के बीच इस संबंध में उभरे मतभेदों को दूर कर लिया गया और उनके बीच देश में युद्धकालीन निवेश को लेकर इस पैकेज पर सहमति बन गई। रिपब्लिकन सीनेट बहुमत के नेता मिच मक्कोन्नेल ने यह कहा। अमेरिका की संसद में सीनेट और प्रतिनिधि सदन में इस विधेयक को हालांकि अभी पारित होना है उसके बाद ही इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिये भेजा जायेगा। इस पैकेज के जरयि अमेरिकीयों के हाथ में सीधे नकदी पहुंचाई जायेगी, छोटे कारोबारियों को अनुदान मिलेगा और बड़ी कंपनियाको अरबों डालर का कर्ज उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ ही बेरोजगार लाभों का भी विस्तार किया जायेगा। सरकार के अलावा अमेरिका के फेडरल रिजर्व की तरफ से 4 हजार अरब डालर की तरलता अर्थव्यवस्था में जारी की जायेगी। फेडरल रिजर्व ने डालर प्रवाह जारी रखने के साथ ही अपनी प्रमुख कर्ज की दर को शून्य के करीब ला दिया है। दुनिया में कुछ विशलेषकों ने जी7 और जी20 की तरफ से सामूहिक प्रतिक्रिया की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि इन देशों को गरीब राष्ट्रों की मदद के लिये आगे आना चाहिये। ये देश अपने धनी समकक्ष देशों के बराबर कर्ज उपलब्ध कराने की क्षमता की बराबरी नहीं कर सकता है। सउदी अरब ने कहा है कि वह जी20 समूह की एक वीडियो कन्फ्रेंसिंग के आयोजन की बात कही है। सउदी अरब इस समय जी20 का अध्यक्ष है। उसने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डानोल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग बृहस्पतिवार को इस शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। जी7 के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक प्रमुखों ने मंगलवार को कहा कि वह एक ''व्यापक और अनुपूरक

पैकेज '' पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इस वचनबद्धता को दोहराया कि वह रोजगार और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये जो भी जरूरी होगा वह सब करेंगे। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने अपने स्तर पर अर्थव्यवस्थाको बचाने के लिये कदम उठाने शुरू किये हैं।

केंद्र ने राज्यों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कारोना पाबंदी से छूट देने की सिफारिश की

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू सार्वजनिक पाबंदियों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के काम काज को बंद न कराने की सलाह दी है और इनकी आपूर्ति निरंतर बनाये रखने को कहा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)के सचिव गुरूप्रसाद महापात्र ने खुदरा दुकानों, दवा दुकानों, विनिर्माण इकाइयों के कर्मचारियों और परिचालकों को अपनी इकाइयों तक जाने की अनुमति देने को कहा है। सचिव ने 23 मार्च के पत्र में कहा है, ''कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिये कई राज्यों में लॉकडाउन किया गया है। कई अन्य एहतियाती कदम उठाये गये हैं। इसको देखते हुए डीपीआईआईटी की तरफ से राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया जाता है कि वे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बाधित या उसे बंद नहीं करें क्योंकि वे खाने-पीने का सामान तैयार करते हैं। साथ ही बिना किसी बाधा के देश के नागरिकों के लिये इन सामानों की आपूर्ति बनाये रखे।'' सचिव ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को साफ-सफाई के कड़े मानदंडों के साथ अपने विनिर्माण संयंत्र खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। धारा 144 या निषेधाज्ञा से छूट वाली इकाइयों में इन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिये कच्चा माल ले जाने वाले वाहनों को भी आने-जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पत्र में सभी खुदरा, किराना, थोक दुकानें और दवा की दुकानों को भी खोलने की अनुमति देने को कहा गया है ताकि आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और लोग अफरातफरी में खरीदारी नहीं करे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।